बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्षः 24 ● अंकः 244 ● नई दिल्ली ● वीरवार 16 जुलाई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्यः 3 रूपया ● पृष्ठः 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागारिक गौतम भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली में यमुना में नहाते वक्त बहे चार किशोर, एक का शव बरामद; तीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

बाहरी दिल्ली। अलीपुर थाना क्षेत्र में यमुना नदी में डूबे चार छात्रों में से एक राहुल का शव बरामद कर लिया गया। बाकी तीन अन्य छात्रों की तलाश में एनडीआरएफ, दमकल विभाग और बोट क्लब की टीमें लगातार यमुना में तलाशी अभियान चला रही हैं। बोट क्लब प्रभारी हरीश कुमार के अनुसार गोताखोरों की मदद से बुधवार को राहुल का शव बरामद किया गया। 15 साल का राहुल पिता सतीश और परिवार के अन्य सदस्य के साथ इब्राहिमपुर गांव में रहता था। कादीपुर के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला राहुल दसवीं कक्षा का छात्र और एनसीसी कैडेट था।

नोएडा के ममूरा गांव में इमारत लगी भीषण आग, चपेट में आने से दो की मौत

नोएडा । यूपी के नोएडा में बुधवार को एक इमारत में भीषण आग लग गई। फेज-3 थाना इलाके के ममूरा गांव स्थित इमारत में लगी आग की चपेट में दो लोगों की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग की शुरुआत एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में हुए धमाके से हुई थी। आग तेजी से फैल गई और आसपास खड़े कई वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। आग लगने के समय भवन के अंदर करीब 50 परिवार मौजूद थे। धुआं और लपटें फैलने से वहां अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग और पुलिस का दल मौके पर पहुंचा। दमकल कर्मियों ने तत्काल बचाव अभियान चलाकर भवन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि, मृतकों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। अग्निशमन विभाग ने कई दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया।

दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया आगे बढ़ी, अंतिम सूची 19 अक्तूबर को

नई दिल्ली । दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची 19 अक्तूबर को प्रकाशित होगी। राजधानी में मतदाता सूची के एसआईआर अभियान के 15 दिन पूरे होने तक चुनाव आयोग घर-घर गणना फॉर्म पहुंचाने में लगभग लक्ष्य हासिल कर चुका है, लेकिन इन्हें ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज करने की रफ्तार अब भी धीमी है। हर आठ में सिर्फ एक फॉर्म ही डिजिटाइज हो पाया है। 14 जुलाई रात आठ बजे तक जारी रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली के 1,45,10,298 मतदाताओं में से 1,43,02,626 यानी 98.57 प्रतिशत मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। इसके मुकाबले केवल 17,66,553 फॉर्म ही ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज किए गए, जो कुल मतदाताओं का 12.17 प्रतिशत है। यानी करीब 1.25 करोड़ फॉर्म अभी डिजिटाइज होने बाकी है। चुनाव आयोग ने इस विशेष अभियान के लिए 30 जून से 29 जुलाई तक का समय निर्धारित किया था। जिलों की बात करें तो आउटर नॉर्थ डिजिटाइजेशन में सबसे आगे है। यहां 25.25 प्रतिशत फॉर्म ऑनलाइन दर्ज किए जा चुके है। इसके बाद दक्षिण-पश्चिम जिले में 17.63 प्रतिशत, सेंट्रल नॉर्थ में 15.41 प्रतिशत, नॉर्थ में 14.70 प्रतिशत और पश्चिम जिले में 14.61 प्रतिशत फॉर्म डिजिटाइज हुए है। दूसरी ओर ओल्ड दिल्ली (7.22 प्रतिशत), पूर्वी दिल्ली (7.25 प्रतिशत) और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली (7.90 प्रतिशत) जैसे जिलों में डिजिटाइजेशन की रफ्तार सबसे धीमी बनी हुई है। हालांकि फॉर्म वितरण के मामले में अधिकांश जिले 98 से 100 प्रतिशत तक पहुंच चुके है। नई दिल्ली जिले में सभी पात्र मतदाताओं तक फॉर्म पहुंचाने का दावा किया गया है, जबकि उत्तर-पूर्व, मध्य, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और अन्य अधिकांश जिले भी 99 प्रतिशत के आसपास पहुंच चुके है। केवल उत्तर-पश्चिम जिला 94.36 प्रतिशत के साथ अपेक्षाकृत पीछे है।

ममता बोलीं- भाजपा चाहती थी मुझे हार्ट अटैक आ जाए, मैं तब तक जिंदा रहूंगी, जब तक उनका अंत न हो जाए

कोलकता । टीएमसी के कई बागी नेताओं ने पार्टी छोड़ने के लिए अभिषेक बनर्जी के कथित मनमाने रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे माहौल में पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के समर्थन में मजबूती से सामने आईं। बुधवार को उन्होंने गद्दारों की ओर से जनता से माफी मांगी और कहा कि न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार ने राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए कभी कोई समझौता किया है। टीएमसी में बढ़ती फूट के बीच अभिषेक बनर्जी के बचाव में अब तक का सबसे मुखर सार्वजनिक बयान देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद अभिषेक को पार्टी पर हमलों का बहाना बना दिया गया है। राजनीतिक लड़ाई छोड़कर राहत हासिल करने के बजाय अभिषेक ने संघर्ष का रास्ता चुना और इसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। फेसबुक लाइव के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को एक बहाना बना दिया गया है। उनके परिवार के सदस्यों को समन भेजा गया। अगर वह चाहते तो राहत पा सकते थे, लेकिन वह लड़ाई के मैदान से भागे नहीं। जिस तरह उन्होंने संघर्ष जारी रखा है, उनकी सभी कमियों को माफ किया जा सकता है।

बागी नेताओं के आरोप क्या हैं?

हाल के हफ्तों में टीएमसी छोड़ने वाले कई वरिष्ठ नेताओं ने अभिषेक बनर्जी पर पार्टी को तानाशाही तरीके से चलाने और संगठन में डर का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं गद्दारों की ओर से जनता से माफी मांगती हूं। मैंने अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए कभी अपनी अंतरात्मा नहीं बेची। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार को लगातार राजनीतिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कभी समझौता करने का रास्ता नहीं चुना।

समझौता करने वालों पर क्या बोलीं?

पार्टी बदलने वाले नेताओं पर परोक्ष हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैंने समझौता किया होता, तो हमें इतनी प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ती। जिन्होंने समझौता किया है, उनके पास अपने कई बैग और सामान है। यह दावा करते हुए कि भाजपा जांच एजेंसियों और पुलिस का इस्तेमाल कर नेताओं पर दबाव बना रही है, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि कई नेताओं ने डर की वजह से पार्टी छोड़ी है। लोकसभा और राज्यसभा में हमारे अभी भी 18 सांसद हैं। जो सांसद सेटिंग कंपनी में शामिल हुए है, उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वे पुलिस से डरते है।

वॉशिंग मशीन वाले बयान का क्या मतलब था?

भाजपा पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी छोड़ने वाले नेता भगवा पार्टी की वॉशिंग मशीन और भाजपा समर्थित टीएमसी के बागी खेमे में जा रहे है। आज जो व्यक्ति (मदन मित्रा) पार्टी छोड़कर गए, उन्होंने कल ही हमें बताया था कि उन्हें और उनके परिवार को समन मिला है। तभी हमें समझ आ गया था कि वे पाला बदल सकते हैं। जिनकी कोई सेटिंग है, वे ही भाजपा की वॉशिंग मशीन में शामिल हो रहे है।

राहुल गांधी को राहत, कोर्ट ने खारिज की निगरानी याचिका; मजिस्ट्रेट के आदेश में हस्तक्षेप से किया इनकार

सुल्तानपुर । गृहमंत्री अमित शाह पर कथित विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। स्पेशल जज राकेश यादव की अदालत ने भाजपा नेता विजय मिश्र की निगरानी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया। इस फैसले से स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित मानहानि मुकदमे की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। अब मामले में 18 जुलाई को सुनवाई होगी। स्पेशल जज ने अपने आदेश में कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित अंतिम बहस की कार्यवाही को रोकना उचित नहीं था। अदालत ने माना कि परिवादी की ओर से दायर निगरानी याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है। यह मामला भाजपा नेता विजय मिश्र ने वर्ष 2018 में दायर किया था। आरोप है कि राहुल गांधी ने अमित शाह के संबंध में विवादित टिप्पणी की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान विजय मिश्र ने 12 मार्च को राहुल गांधी की आवाज का नमूना जांच कराने की मांग की थी। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने 2 मई को यह अर्जी खारिज कर दी थी। उन्होंने जमानतनामा प्रस्तुत करने और अंतिम बहस आगे बढ़ाने का आदेश दिया था। विजय मिश्र ने इस आदेश को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। बुधवार को स्पेशल जज ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

मैं भारत से हूं मुसलमान हूं -जबाव सुनकर यूएस में भारतीय शख्स के ऊपर 15 बार किया धारदार चाकू से हमला

इंटरनेशनल डेस्क । अमेरिका के यूटा राज्य से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां मजहबी नफरत के चलते एक भारतीय मूल के व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया। वेस्ट वैली सिटी के वैली फेयर मॉल में 48 वर्षीय पीटर माइकल लार्सन नामक व्यक्ति ने एक भारतीय स्टोर वर्कर, सोहेल पर 15 बार चाकू से हमला किया। हैरानी की बात यह है कि हमला करने से पहले आरोपी ने बाकायदा पीड़ित से उसका धर्म पूछा था।

मैं भारत से हूं.. मुसलमान हूं

चश्मदीद गवाह और पास के ज्वेलरी स्टोर में काम करने वाली लूना नुनेज के अनुसार, लार्सन ने सोहेल के पास जाकर बातचीत शुरू की और पूछा कि वह कहां से है। सोहेल ने जवाब दिया, मैं इंडिया से हूं, मेरा नाम सोहेल है। इसके बाद जब लार्सन ने पूछा कि क्या वह मुस्लिम है, तो सोहेल के हां कहते ही लार्सन ने उस पर अंधाधुंध चाकू चलाने शुरू कर दिए।

आरोपी ने कबूला जुर्म -मुस्लिम था, इसलिए मारना चाहता था

पुलिस की पूछताछ में आरोपी पीटर माइकल लार्सन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक, लार्सन ने स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर सोहेल को निशाना बनाया क्योंकि वह मुस्लिम था और वह उसे जान से मार डालना चाहता था। फिलहाल लार्सन पर हत्या की कोशिश और खतरनाक हथियार रखने के आरोप लगाए गए है और उसे साल्ट लेक काउंटी जेल में रखा गया है।

परिवार का इकलौता सहारा है सोहेल

सोहेल के दोस्तों ने उसे एक बेहद मेहनती और हंसमुख इंसान बताया है। उसके दोस्त मोहम्मद अदनान, जिन्होंने सोहेल को हाल ही में मैनेजर के पद पर प्रमोट किया था।

अमेरिकी सेना ने दिन के उजाले में शुरू किए हवाई हमले

दुबई। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने ईरान को निशाना बनाकर हवाई हमलों का नया दौर शुरू कर दिया है। सेना ने बुधवार को दिन के उजाले में इन हमलों की शुरुआत की। यह हमलों की बढ़ती रफ्तार का ही एक हिस्सा है। अमेरिकी सेना की मध्य कमान (सेंटकॉम) ने ऑनलाइन जारी एक बयान में इस बात की पुष्टि की कि हमले शुरू कर दिए गए है। पिछले कुछ दिनों से किए जा रहे हमलों में अमेरिका ने ईरान को केवल रात के समय निशाना बनाया था। सेंटकॉम ने कहा, इन हमलों का मकसद ईरानी सेना की उन सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल वह होर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने के लिए कर रही है। ये हमले ऐसे समय में किए गए है, जब ईरान और अमेरिका के बीच हुआ अंतरिम समझौता पूरी तरह से टूट चुका है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के रडार और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाते हुए ग्रेटर टुनब द्वीप पर हमला किया है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से नौसैनिक नाकाबंदी लगा दी है और आज से हवाई हमले तेज कर दिए है। अमेरिका ने यह कार्रवाई तेहरान की ओर से होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार, अमेरिकी हमलों में ईरानी सेना की एक बैरक को निशाना बनाया गया, जिसमें सात सैनिकों की मौत हो गई और पूरे देश में 260 से अधिक लोग घायल हुए है।

सम्पादकीय...

डूब रहे शहर

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से लेकर दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम, बेंगलुरु, सूरत, पटना, जयपुर, लखनऊ हो या फिर अन्य कोई शहर जरा सी बारिश होते ही सड़कें पानी से लबालब हो जाती हैं। यह हाल उन शहरों का है जहां सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर भारी-भरकम बजट खर्च करने की बात करती है लेकिन तबाही का मंजर हर साल सामने आकर खड़ा हो जाता है और सारी तैयारियां इससे रोकने में नाकाफी साबित होती है। क्या आपने कभी सोचा कि सामान्य से थोड़ी-सी ज्यादा बारिश होते ही हमारे देश के छोटे-बड़े तमाम शहर कुछ ही घंटों में 'तालाब' बन जाते है, आखिर इसकी वजह क्या है? देश में हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे किए जाते हैं लेकिन तमाम दावे मौका पड़ने पर हवा-हवाई क्यों हो जाते हैं? देशभर में मानसून के दौरान होने वाला जलभराव सिर्फ भारी बारिश का नतीजा नहीं, बल्कि खराब शहरी योजना, पुराने ड्रेनेज सिस्टम और अनियोजित विकास का परिणाम भी है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत के अधिकांश शहर अत्यधिक तेज बारिश के कारण होने वाली शहरी बाढ़ से प्रभावित होते हैं। प्राकृतिक जल निकासी के खत्म होने, नालों में गाद और कचरे के जमा होने, विभागों के बीच समन्वय की कमी और दशकों पुराने ड्रेनेज सिस्टम के कारण हर साल शहर पानी में डूब जाते हैं। देश की आबादी बढ़ती जा रही है। पेड़-पौधे लगातार कम होते जा रहे हैं। पुराने शहरों में नई-नई इमारतों का निर्माण हो रहा है लेकिन जल निकासी की नई व मजबूत व्यवस्था पर काम नहीं किया जा रहा है। कंक्रीट बढ़ने के चलते जमीन पानी नहीं सोख पा रही है। शहरों में जल निकासी का एक ही उपाय है कि ड्रेनेज लाइन से पानी को इकट्ठा कर नदियों में छोड़ा जाए। हमारे यहां ड्रेनेज सदियों से वही सिस्टम चला आ रहा है। इसमें भी 60 से 70 प्रतिशत ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक होते हैं। इसलिए जब बारिश होती है तो पानी की प्रॉपर निकासी न होने से बैकफ्लो के तौर पर वापस शहरों में घुसता है। ज्यादातर छोटे-बड़े शहरों में बरसात के पानी की निकासी के लिए स्टॉर्म वॉटर ड्रेन (बरसाती नाले) बनी हुई हैं। जब बनाई जाती हैं, तब ये ठीक होती हैं। बाद में उनमें मिट्टी और कचरा भर जाता है। दूसरी समस्या ये है कि स्टॉर्म वॉटर ड्रेन से ही सीवेज की लाइन भी जोड़ दी जाती है। जबकि ड्रेनेज तकनीक के मुताबिक, ड्रेन पाइप और सीवर पाइप अलग-अलग होने चाहिए। ऐसे में जब तेज बारिश होती है तो स्टॉर्म वॉटर ड्रेन से पानी सीवर लाइन में आता है या गलियों व सड़कों पर। यही कारण है कि बारिश में सीवर ओवरफ्लो होते हैं, जिससे दूषित पानी गलियों और सड़कों में भर जाता है। जरा सी बारिश में शहरों के 'तालाब' बनने की बड़ी वजह टाउनशिप डेवलपमेंट प्लानिंग में भविष्य और डेंसिटी दोनों पर ध्यान न दिए जाना है। डेंसिटी प्लानिंग यानी किसी क्षेत्र या शहर विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या के आधार पर योजना बनाना लेकिन योजना बनाने वाले आगामी सालों में बढ़ती आबादी का अनुमान लगाए बिना ही बुनियादी ढांचा बना देते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की ओर की गई रिसर्च पुख्ता करती है। सीएसई की रिसर्च में कहा गया है कि देश के करीब 66 फीसदी से ज्यादा शहरों में अर्बन प्लानिंग खराब है, इस कारण बारिश के दौरान बाढ़ व जलभराव का खतरा रहता है। बारिश के चलते शहरों में होने वाले जलभराव से सबसे ज्यादा दिक्कत आम नागरिकों को होती है। आमजन के वक्त ऊर्जा और उत्पादकता की बर्बादी होती है। जलभराव के कारण कई-कई घंटों का जाम लग जाता है, जिससे न सिर्फ काम के घंटे बर्बाद होते हैं, बल्कि ईंधन जलता है। दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिनमें संपत्ति, वाहन और जान की हानि होती है। इस सर्वे में 64 फीसदी लोगों ने माना कि जलभराव का उनकी नौकरी और काम के घंटों पर भी बुरा असर पड़ता है, कई बार तो नौकरी जाने की नौबत आ जाती है। बारिश के पानी से होने वाले जलभराव के कारण हर साल हमारे शहरों को हजारों करोड़ रुपये का भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। भारतीय स्टेट बैंक की इकोरैप रिपोर्ट के अनुसार केवल एक मानसूनी सीजन में बाढ़ और बारिश के कारण देश को 10,000 से 15,000 करोड़ रुपये का नुकसान तक हो जाता है। 'यूनाइटेड स्टेट ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी' और केपीएमजी हर दशक में बाढ़ से हुए नुकसान के आंकड़े जारी करती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि पिछले 10 साल में अकेले मुंबई में जलभराव से 14 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। हालांकि अगर इस नुकसान को राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो यह आंकड़ा काफी बड़ा निकलेगा। देश के छोटे-बड़े शहरों में जलभराव अब प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि प्रशासनिक विफलता का प्रतीक बन चुका है। विडंबना यह है कि किन स्थानों पर हर साल बारिश में पानी भरता है, इसके कारण क्या है और समाधान कैसे संभव है। यह सब संबंधित विभागों को अच्छे तरह पता होता है। इसके बावजूद संबंधित विभागों के बीच जिम्मेदारी तय करने के बजाय एक-दूसरे पर जवाबदेही डालने का सिलसिला जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि इस समस्या का स्थाई समाधान क्या है? क्या अन्य देशों के मॉडल इस समस्या को सुलझाने में हमारी मदद कर सकते है? जीन की तर्ज पर भारतीय शहरों को 'स्पंज सिटी' के रूप में विकसित करने की जरूरत है, जहां पार्क, छतें और फुटपाथ पानी को सोखने वाले बनाए जाएं। जापान की राजधानी टोक्यो में बाढ़ को रोकने के लिए सुरंग बनाई गई है, जिन्हें 'फ्लड टनल्स' कहा जाता है। जब भी बाढ़ के हालात बनते है तो फ्लड टनल्स के जरिए पानी इन टैंकों में चला जाता है। टैंक में भर जाने पर चार बड़ी टर्बाइन इस पानी को नदी में ले जाने में मदद करती है। ब्रिटेन में सस्टेनेबल अर्बन ड्रेनेज सिस्टम से बारिश के पानी का प्रबंधन किया जा रहा है। शहर में पानी सोखने वाली जगहें और बारिश का पानी जमा करने वाले छोटे-छोटे तालाब बनाए गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय शहर बढ़ती आबादी के साथ-साथ भौतिक बुनियादी ढांचे की मांग को पूरा करने की दोहरी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इसकी वजह से वह मौसम की घटनाओं, यहां तक कि सामान्य बारिश के लिए भी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हमेशा मानसून को दोष नहीं दे सकते। बारिश और बाढ़ से निपटने के लिए जल निकासी की मजबूत व्यवस्था बनानी होगी। शहरी प्लानिंग के लिए बजट को प्राथमिकता के रूप में लेना होगा। हर शहर की अपनी ऊंचाई और जनसंख्या होती है। इसलिए शहर की आबादी, रिहायशी इलाकों और अगले 100 साल के अनुमान को ध्यान में रखते हुए ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाना चाहिए। वहीं हर साल बारिश के मौसम से पहले ड्रेनेज ऑडिट कराया जाए। नेचुरल ड्रेनेज कैपेसिटी बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए।

'रैड कॉरिडोर' से वापसी का रास्ता

वरिष्ठ नेताओं की हत्या, गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण सहित विभिन्न तरीकों से समाप्त किया जा रहा था। इकाइयों के बीच संचार तेजी से कठिन होता जा रहा था और रैंकों में अनिश्चितता फैल गई थी। जिस आत्मविश्वास ने कभी आंदोलन को जीवित रखा था, उसने इसके दीर्घकालिक अस्तित्व को लेकर संदेहों को जन्म दे दिया था। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में, पापा राव और 18 अन्य माओवादियों ने 24 मार्च, 2026 को आत्मसमर्पण कर दिया। सुरक्षा अधिकारी इस घटना को हाल के वर्षों में उग्रवाद के लिए सबसे बड़े झटकों में से एक मानते हैं। अपने तत्काल प्रभाव से परे, इसने माओवादी रैंकों को यह संदेश दिया कि अनुभवी कमांडर भी अब आश्वस्त नहीं थे कि आंदोलन अनिश्चित काल तक खुद को बनाए रख सकता है। बाद के महीनों में, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में और अधिक कैडरों ने आत्मसमर्पण किया। पुनर्वास प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, सरकार ने पापा राव को कड़ी निगरानी में रखा है।

सालों तक, दक्षिण बस्तर के जंगलों में रहने वाले ग्रामीण उसका नाम लेने से कतराते थे। माओवादी आंदोलन के इस गढ़ में, पापा राव उसके वर्चस्व का प्रतीक था। किसी गांव में उसकी मौजूदगी यह तय कर सकती थी कि किससे पूछताछ की जाएगी, किसे सजा दी जाएगी और सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, कौन पुलिस का मुखबिर होने के लगातार संदेह के साए में जिएगा। डर ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। हालांकि, आज वह डर अपनी चमक खो चुका है। पापा राव को अब सुरक्षा बलों द्वारा पीछा किए जाने का डर नहीं है। इसकी बजाय, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर है, जिनसे उसने सालों तक लड़ाई लड़ी थी। यह बदलाव इसलिए नहीं है क्योंकि अतीत मिट गया है, बल्कि इसलिए है, क्योंकि उस अतीत के परिणाम अपरिहार्य हो गए हैं। जो ग्रामीण कभी माओवादी प्रभाव में रहते थे, उन्होंने उसे माफ नहीं किया। पंचायत सदस्य भूमिगत आंदोलन के दौरान उसके वर्षों से जुड़ी हिंसा को लेकर गहरा आक्रोश रखते हैं। सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि बिना सुरक्षा के, उसकी जान को खतरा पुलिस से नहीं, बल्कि उन लोगों से होगा, जिन्हें लगता है कि कभी न्याय नहीं मिला। उनका कहना है कि पीड़ितों में से कई सामान्य ग्रामीण थे, जिन पर पुलिस मुखबिर होने का झूठा आरोप लगाया गया था। कुछ तो किशोर थे। इसके जवाब में, प्रशासन ने एक असामान्य रुख अपनाया है। अधिकारियों ने ग्रामीण नेताओं से संपर्क किया और उनसे बदला न लेने का आग्रह किया है। उनका संदेश सीधा है-एक बार जब कोई विद्रोही औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर देता है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर आ जाती है। कोई इस नीति से सहमत हो या नहीं, यह पुनर्वास के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को दर्शाता है कि हथियार डालने वालों से किए गए वादों को पूरा किया जाना चाहिए, यदि दूसरों से भी ऐसा ही करने की उम्मीद की जाती है। माओवादी संगठन के रैंकों में पापा राव का उभार लगातार प्रगति के साथ हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक एरिया कमेटी सदस्य के रूप में की और बाद में 2025 में दक्षिण उप-जोनल कमांडर के पद पर पहुंचे। सुरक्षा एजेंसियां उन पर वर्षों से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) और सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) सहित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के खिलाफ कई हमलों में बड़ी भूमिका निभाने का आरोप लगाती हैं। इन अभियानों के परिणामस्वरूप कुल मिलाकर 100 से अधिक सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए। हालांकि, 2026 की शुरुआत तक, जिस संगठन को उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था, वह अभूतपूर्व तनाव का सामना कर रहा था। महीनों तक चले लगातार उग्रवाद-विरोधी अभियानों ने माओवादी संरचनाओं के लिए उपलब्ध परिचालन क्षेत्र को काफी कम कर दिया था। वरिष्ठ नेताओं की हत्या, गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण सहित विभिन्न तरीकों से समाप्त किया जा रहा था। इकाइयों के बीच संचार तेजी से कठिन होता जा रहा था और रैंकों में अनिश्चितता फैल गई थी। जिस आत्मविश्वास ने कभी आंदोलन को जीवित रखा था, उसने इसके दीर्घकालिक अस्तित्व को लेकर संदेहों को जन्म दे दिया था। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में, पापा राव और 18 अन्य माओवादियों ने 24 मार्च, 2026 को आत्मसमर्पण कर दिया। सुरक्षा अधिकारी इस घटना को हाल के वर्षों में उग्रवाद के लिए सबसे बड़े झटकों में से एक मानते हैं। अपने तत्काल प्रभाव से परे, इसने माओवादी रैंकों को यह संदेश दिया कि अनुभवी कमांडर भी अब आश्वस्त नहीं थे कि आंदोलन अनिश्चित काल तक खुद को बनाए रख सकता है। बाद के महीनों में, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में और अधिक कैडरों ने आत्मसमर्पण किया। पुनर्वास प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, सरकार ने पापा राव को कड़ी निगरानी में रखा है। यद्यपि वह अपने ऊपर घोषित इनाम राशि (25 लाख रुपए) के साथ-साथ अपनी ए.के.-47 राइफल सौंपने के लिए 3 लाख रुपए प्राप्त करने के पात्र हैं, लेकिन ये लाभ पुनर्वास ढांचे के साथ उनके निरंतर अनुपालन पर निर्भर है। अधिकारी उन्हें पूरी तरह से पुनर्वासित मानने से पहले उनके आचरण की निगरानी करने का इरादा रखते हैं। यह रेखांकित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उनके आत्मसमर्पण को दोषमुक्ति नहीं समझा जाना चाहिए। एक आत्मसमर्पण पीड़ितों द्वारा झेली गई पीड़ा या अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के दर्द को मिटा नहीं सकता। इसके अलावा, यह भूमिगत रहने के दौरान उनके कार्यकाल में की गई हिंसा के आरोपों को भी खारिज नहीं करता। हालांकि, उनके आत्मसमर्पण का महत्व किसी एक कमांडर के भाग्य से कहीं अधिक बड़ा है। यह एक नए चरण में प्रवेश कर रहे संघर्ष को दर्शाता है-ऐसा चरण, जहां कभी डर के बल पर चलाया जाने वाला वर्चस्व अब कमजोर हो रहा है, जहां कभी अपनी शर्तें तय करने वाले कमांडर सशस्त्र संघर्ष की बजाय बातचीत का विकल्प चुन रहे हैं और जहां राज्य की सबसे बड़ी चुनौती अब केवल किसी उग्रवाद को हराना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जो लोग इसे छोड़ चुके हैं, वे कभी भी वापस लौटने के लिए मजबूर महसूस न करें। वर्तमान में, पापा राव का जीवन एक ऐसी वास्तविकता से परिभाषित होता है, जो कभी अकल्पनीय लगती थी। जो व्यक्ति कभी डर पैदा करता था, वह आज इसलिए जीवित है, क्योंकि दूसरे लोग डर को उस तक पहुंचने से रोक रहे हैं।

बिलावल !

भारत ने पिछले सप्ताह जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर बने बगलीहार बांध के तीन गेट खोलकर पानी पाकिस्तान की ओर छोड़ा तो पाकिस्तान बौखला गया। अभी तक तो पानी नहीं छोड़ने पर खफा था और अब उसकी सेना से लेकर उसके नेता तक खौफनाक धमकी के मूड में आ गए हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो बिलबिला रहे हैं जो सीधे-सीधे जंग की भाषा बोल रहे हैं, वो भूल गए 1971 जब 93 हजार से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की सेना के सामने सरेंडर किया था। पानी के लिए तीसरे विश्व युद्ध के मुहावरे का उपयोग काफी समय से होता रहा है लेकिन पाकिस्तानी तो सचमुच युद्ध की बात करने लगे है। मामला यह है कि भारत की ओर से पाकिस्तान की ओर जाने वाली नदियों के पानी को लेकर दोनों देशों में 1960 से ही एक संधि रही है। इसके तहत रावी, सतलुज और ब्यास नदी के पानी पर पूरा हक भारत का है, जबकि झेलम, सिंधु और चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान को मिलता है। यदि इन नदियों में पानी ज्यादा आ जाए तो भारत बाढ़ की पूर्व सूचना पाकिस्तान को देता था, मगर पिछले साल पहलगाम की आतंकी घटना के बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। भारत ने जल संधि को निलंबित कर दिया, अब भारत इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि नदियों में पानी को लेकर किसी भी तरह की जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा करे। इसलिए बगलीहार बांध का पानी छोड़ने से पहले सूचना नहीं दी गई। पाकिस्तान की करीब 90 प्रतिशत खेती सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है, उसके पास इतने डैम नहीं है कि वह नदी के पानी को जरूरत के वक्त उपयोग के लिए संभाल कर रख सके, इसलिए गर्मी के दौरान उसे बहुत परेशानी हुई। वह दुनियाभर में गिड़गिड़ा रहा है, संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिख रहा है। मगर भारत अडिग है कि आतंकवाद समाप्त करो, तभी बातचीत होगी। तो अब वह भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है, सिंधु जल समझौता भारत की ओर से निलंबित किए जाने के बाद पिछले साल पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई थी जिसमें कहा गया था कि पानी रोकने या पानी का रास्ता बदलने की कोशिश को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। अब फिर जनरल आसिम मुनीर की अध्यक्षता में सेना की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पाकिस्तानी सेना हक के लिए लड़ेगी। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने भी कहा था कि पानी रोकने की कोशिश को युद्ध जैसी कार्रवाई माना जाएगा। यानी सबकी भाषा जंग की ही है। मगर बिलावल भुट्टो आगे निकल गए, उन्होंने गिलगित की जनसभा में कहा कि भारत सिंधु नदी को हथियार के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। यदि जंग लड़नी पड़े तो जंग लड़ने को तैयार है। बिलावल की इस बात पर मुझे हंसी आ रही है, यदि तुम्हारे नाना और तुम्हारी मां जिंदा होती तो तुम्हें समझाते कि पाकिस्तान के पास जंग की औकात नहीं है। मि. भुट्टो, हम बड़े दिल वाले लोग है मगर हम किसी की हेकड़ी भी बर्दाश्त नहीं करते, तुम्हारा देश आतंकवाद को जिस दिन पालना-पोसना बंद कर देगा, भारत उसी दिन उसे माफ कर देगा। बुडापेस्ट में सड़क पर घूमते हुए मुझे सोने जैसे चमचमाते हुए गटर के ढक्कन दिखाई दे रहे थे।

मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना ने आगरा के किसान श्री मतेन्द्र सेंगर की तकदीर बदली

आधुनिक एवं मानकीकृत कैटल शेड का निर्माण, वैज्ञानिक पशुपालन व्यवस्था तथा आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास भी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके साथ ही लाभार्थी के पास डेयरी इकाई के लिए लगभग 0.20 एकड़ भूमि तथा चारा उत्पादन के लिए लगभग 0.80 एकड़ भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है। इन प्रावधानों का उद्देश्य केवल डेयरी इकाई स्थापित करना नहीं, बल्कि उसे दीर्घकाल तक सफल और लाभकारी बनाए रखना है। आज श्री मतेन्द्र सेंगर की सफलता इस बात का सशक्त प्रमाण है कि यदि सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्र तक पहुंचे और उन्हें आधुनिक तकनीक तथा वैज्ञानिक प्रबंधन का सहयोग मिले, तो ग्रामीण परिवारों की आर्थिक तस्वीर बदली जा सकती है। उनकी कहानी केवल एक किसान की सफलता नहीं, बल्कि उन हजारों किसानों के लिए प्रेरणा है जो कृषि के साथ पशुपालन को जोड़कर अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने, स्वदेशी गोवंश के संरक्षण, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

उत्तर प्रदेश में कृषि और पशुपालन सदियों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दो मजबूत आधार रहे हैं। जहां खेती किसानों की आजीविका का प्रमुख साधन है, वहीं डेयरी व्यवसाय उन्हें नियमित आय का स्थायी स्रोत उपलब्ध कराता है। बदलते समय के साथ कृषि को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए आवश्यक हो गया है कि किसानों को ऐसे वैकल्पिक आय स्रोत उपलब्ध कराए जाएं, जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता दोनों प्रदान करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार इसी उद्देश्य के साथ किसानों और पशुपालकों को आधुनिक डेयरी व्यवसाय से जोड़ने के लिए अनेक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही है। नन्द बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत संचालित मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना ऐसी ही एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो किसानों के जीवन में समृद्धि की नई कहानी लिख रही है। जनपद आगरा के निवासी श्री मतेन्द्र सेंगर, पिता श्री उदयवीर सिंह, लंबे समय से कृषि एवं पशुपालन से जुड़े रहे हैं। खेती से होने वाली आय परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रमुख आधार थी, लेकिन अन्य छोटे किसानों की तरह उनके सामने भी आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने की चुनौती थी। ऐसे समय में उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना की जानकारी मिली। योजना के अंतर्गत चयनित होने के बाद उन्होंने आधुनिक डेयरी व्यवसाय की दिशा में कदम बढ़ाया और यही निर्णय उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। वर्ष 2024-25 में उन्होंने योजना के अंतर्गत 23.60 लाख रुपये की लागत से आधुनिक डेयरी इकाई स्थापित की। इस परियोजना पर उन्हें कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुआ, जिससे डेयरी व्यवसाय प्रारंभ करना आर्थिक रूप से सहज और व्यावहारिक बन गया। योजना के तहत उन्होंने 10 स्वदेशी नस्ल की साहीवाल एवं गिर गायों पर आधारित आधुनिक डेयरी इकाई स्थापित की। सरकार द्वारा प्राप्त सहयोग ने उन्हें न केवल आर्थिक संबल दिया, बल्कि आधुनिक पशुपालन अपनाने का आत्मविश्वास भी प्रदान किया। डेयरी इकाई की स्थापना के बाद श्री मतेन्द्र सेंगर ने वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित पशुपालन पद्धतियों को अपनाया।

पशुओं के संतुलित पोषण, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, स्वच्छ रख-रखाव और आधुनिक प्रबंधन के कारण उनकी डेयरी की उत्पादकता लगातार बढ़ी। वर्तमान में उनकी डेयरी से प्रतिदिन लगभग 100 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। नियमित दुग्ध उत्पादन और प्रभावी विपणन व्यवस्था के कारण उनकी औसत वार्षिक आय लगभग 18 लाख रुपये तक पहुंच गई है।

इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, बल्कि खेती के साथ पशुपालन भी आय का स्थायी और भरोसेमंद स्रोत बन गया है। इस सफलता का प्रभाव केवल उनकी आय तक सीमित नहीं रहा। आधुनिक डेयरी इकाई के संचालन से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। पशुओं की देखभाल, दुग्ध संग्रहण, चारा प्रबंधन और अन्य गतिविधियों से आसपास के लोगों को भी रोजगार मिलने लगा है। इस प्रकार यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार को भी प्रोत्साहित कर रही है। श्री मतेन्द्र सेंगर का मानना है कि यदि उन्हें सरकार की इस योजना का सहयोग नहीं मिला होता, तो इतनी बड़ी आधुनिक डेयरी इकाई स्थापित करना संभव नहीं था। वे अपनी सफलता का श्रेय उत्तर प्रदेश सरकार तथा दुग्धशाला विकास विभाग को देते हुए कहते हैं कि मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना ने उन्हें केवल आर्थिक सहायता ही नहीं दी, बल्कि आत्मविश्वास के साथ एक सफल डेयरी उद्यमी बनने का अवसर भी प्रदान किया।

आज वे अन्य किसानों और पशुपालकों को भी आधुनिक डेयरी व्यवसाय अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार की यह योजना स्वदेशी गोवंश के संरक्षण और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के अंतर्गत साहीवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगातिरी जैसी स्वदेशी नस्लों पर आधारित हाईटेक डेयरी इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत10 स्वदेशी गायों की डेयरी इकाई के लिए 23.60 लाख रुपये की अनुमानित परियोजना लागत निर्धारित की गई है, जिसमें 15 प्रतिशत लाभार्थी अंश, 35 प्रतिशत बैंक ऋण तथा अधिकतम 50 प्रतिशत (11.80 लाख रुपये तक) अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। अनुदान की राशि दो समान किस्तों में दी जाती है, जिससे लाभार्थियों को डेयरी इकाई स्थापित करने में आर्थिक सुविधा मिलती है। इस योजना के अंतर्गत खरीदी जाने वाली गायों का प्रदेश के बाहर से अधिकृत ब्रीडिंग ट्रैक्टर के माध्यम से क्रय, सभी पशुओं की ईयर टैगिंग तथा बीमा कराना अनिवार्य किया गया है। आधुनिक एवं मानकीकृत कैटल शेड का निर्माण, वैज्ञानिक पशुपालन व्यवस्था तथा आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास भी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके साथ ही लाभार्थी के पास डेयरी इकाई के लिए लगभग 0.20 एकड़ भूमि तथा चारा उत्पादन के लिए लगभग 0.80 एकड़ भूमि उपलब्ध होना आवश्यक है। इन प्रावधानों का उद्देश्य केवल डेयरी इकाई स्थापित करना नहीं, बल्कि उसे दीर्घकाल तक सफल और लाभकारी बनाए रखना है। आज श्री मतेन्द्र सेंगर की सफलता इस बात का सशक्त प्रमाण है कि यदि सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्र तक पहुंचे और उन्हें आधुनिक तकनीक तथा वैज्ञानिक प्रबंधन का सहयोग मिले, तो ग्रामीण परिवारों की आर्थिक तस्वीर बदली जा सकती है। उनकी कहानी केवल एक किसान की सफलता नहीं, बल्कि उन हजारों किसानों के लिए प्रेरणा है जो कृषि के साथ पशुपालन को जोड़कर अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने, स्वदेशी गोवंश के संरक्षण, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। मिनी नन्दिनी कृषक समृद्धि योजना इसी संकल्प का प्रभावी उदाहरण है, जिसने अनेक किसानों को रोजगार, सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया मार्ग दिखाया है।

'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' योजना से मेरठ के खेल सामग्री उद्योग को वैश्विक पटल पर मिली उड़ान

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में मेरठ का खेल सामग्री उद्योग हमेशा से एक गौरवशाली अध्याय रहा है। यहाँ के हुनरमंद कारीगरों और उद्यमियों ने क्रिकेट के बल्लों से लेकर एथलेटिक्स के विश्वस्तरीय उपकरणों तक, अपनी अद्वितीय कला का लोहा दुनिया भर में मनवाया है। इस पारंपरिक हुनर को आधुनिकता की रफ्तार देने और वैश्विक पटल पर और अधिक मजबूती से स्थापित करने में प्रदेश सरकार की 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ओडीओपी) यानी 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना एक बड़े उत्प्रेरक के रूप में उभरी है। प्रदेश सरकार की इस दूरदर्शी नीति ने मेरठ के खेल उद्योग को न केवल नई वित्तीय संजीवनी प्रदान की है, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के असीम द्वार भी खोल दिए हैं। इधर कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे और वित्तीय सहायता में जो अभूतपूर्व तेजी आई है, उसने इस पूरे क्षेत्र की उत्पादन क्षमता और आर्थिक ताने-बाने को अभूतपूर्व उत्कर्ष प्रदान किया है। वित्तीय मोर्चे पर ओडीओपी योजना के क्रियान्वयन ने जमीन पर बेहद ठोस और दूरगामी परिणाम दिखाए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के अनुसार, खेल सामग्री निर्माण से जुड़े उद्योगों को तीव्र रफ्तार देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न बैंकिंग संस्थानों के समन्वय से एक सुदृढ़ वित्तीय ढांचा तैयार किया गया। इसके अंतर्गत जिले के लगभग 104 चिन्हित खेल सामग्री उत्पादकों और उद्यमियों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 135 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत कर वितरित किया गया। इस भारी-भरकम राशि ने छोटे और मझोले स्तर के कारखानों को अपनी उत्पादन तकनीक को आधुनिक बनाने तथा कच्चे माल की उपलब्धता को सुचारू करने में अभूतपूर्व मदद की है। इसके साथ ही, इन लाभार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासन द्वारा करीब 12 करोड़ रुपये की भारी सब्सिडी (अनुदान सहायता) सीधे प्रदान की गई, जिससे उद्यमियों के ऊपर से कर्ज के बोझ को काफी कम कर दिया है। इस बड़े पैमाने पर मिली वित्तीय मदद का सीधा सकारात्मक असर मेरठ के औद्योगिक मानचित्र पर दिखाई देने लगा है। करीब 104 स्वीकृत आवेदनों के माध्यम से खेल सामग्री क्षेत्र में व्यापक स्तर पर औद्योगिक विस्तार हुआ है। वित्तीय सहायता के बल पर जिले में पहले से संचालित 100 से अधिक औद्योगिक इकाइयों ने अपनी क्षमता का विस्तार करते हुए नई मशीनें स्थापित की है और आधुनिक तकनीक को अपनाया है। इसके समानांतर, प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित इस अनुकूल माहौल से प्रेरित होकर क्षेत्र में लगभग 80 नए सूक्ष्म और लघु उद्योगों की सफल स्थापना हुई है। नए उद्यमों के आगमन से बाजार में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हुई है और निर्यात की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ओडीओपी योजना ने पारंपरिक रूप से चले आ रहे पारिवारिक व्यवसायों को कॉर्पोरेट रूप में ढलने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पाद तैयार करने की दिशा में एक नया हौसला और सामर्थ्य दिया है। इस सफलता की निरंतरता को और आगे ले जाने के लिए प्रदेश सरकार ने चालू सत्र के लिए और भी बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। खेल सामग्री उद्योग की बढ़ती मांग और उत्पादकों के भारी उत्साह को देखते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुदान की कुल राशि को बढ़ाकर 14.5 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में योजना का दायरा भी काफी विस्तृत किया जा रहा है, जिसके तहत लगभग 360 नए और पुराने उद्यमियों को सीधे तौर पर लाभान्वित करने की कार्ययोजना बनाई गई है। इस नीति के अंतर्गत ऋण लेने वाले उद्यमियों को कुल परियोजना लागत पर 20 से 25 प्रतिशत तक की बड़ी सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये तक तय की गई है।

इस कल्याणकारी व्यवस्था से नए स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों को बिना किसी बड़े आर्थिक-मानसिक दबाव के बाजार में उतरने की बेहतरीन सहूलियत मिल रही है। प्रशासनिक स्तर पर इस पूरी प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी, त्वरित और सुलभ बनाया गया है ताकि वास्तविक कारीगरों और उद्यमियों को बिना किसी बाधा के शत-प्रतिशत लाभ मिल सके।

जिला प्रशासन के स्तर पर आवेदनों की गहन स्क्रूटनी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सहायता सही हकदार तक पहुँच रही है। सिंगल विंडो सिस्टम और बैंकों के साथ बेहतर समन्वय के कारण अब उद्यमियों को ऋण और सब्सिडी के लिए लंबी औपचारिकताओं से मुक्ति मिल गई है। उद्यमी अपनी पसंद और सुगमता के अनुसार किसी भी व्यावसायिक बैंक से ऋण प्राप्त कर इस योजना का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। प्रशासन की इस सक्रियता और नीतिगत सरलता के कारण ही पिछले वर्ष जनपद मेरठ में प्राप्त हुए कुल 238 आवेदनों में से योग्य पात्रों का चयन कर उन्हें त्वरित गति से मुख्यधारा से जोड़ा जा सका।

यह महत्वाकांक्षी योजना केवल उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक पहलू स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन से जुड़ा है। जब एक नया उद्योग स्थापित होता है या पुराने उद्योग का विस्तार होता है, तो उसमें डिजाइनरों, कारीगरों, पैकेजिंग विशेषज्ञों और लॉजिस्टिक्स से जुड़े सैकड़ों लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष काम मिलता है। मेरठ के खेल उद्योग ने स्थानीय स्तर पर हजारों अकुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों को सम्मानजनक आजीविका प्रदान की है। ओडीओपी योजना के माध्यम से मिल रहे वित्तीय सहयोग ने क्षेत्र से श्रम पलायन को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि अब स्थानीय स्तर पर ही बेहतर कार्यदशाएं और उचित पारिश्रमिक उपलब्ध हो रहा है।

इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत शासन द्वारा मिलने वाले विशेष प्रशिक्षण और टूलकिट वितरण कार्यक्रमों ने कारीगरों की कार्यकुशलता और कौशल को निखारने का भी काम किया है। वैश्विक बाजार की बात करें तो मेरठ के बने क्रिकेट बैट, लेदर गेंदें, सुरक्षात्मक गियर और जिम के उपकरण पहले से ही दुनिया के कई देशों में निर्यात किए जाते रहे हैं। लेकिन ओडीओपी योजना के लागू होने के बाद ब्रांडिंग और मार्केटिंग को जो नया सरकारी संरक्षण और आयाम मिला है, उसने अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के बीच मेरठ के उत्पादों की साख को और अधिक पुख्ता कर दिया है। सरकारी स्तर पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में ओडीओपी के तहत मेरठ के खेल उत्पादों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाता है, जिससे स्थानीय उत्पादकों को सीधे वैश्विक खरीदार (बायर्स) मिल रहे हैं। इस सीधे जुड़ाव से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है और वास्तविक लाभ सीधे उत्पादक और कारीगर के बैंक खातों तक पहुँच रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। प्रदेश सरकार के प्रयासों से मेरठ का खेल उद्योग अब पारंपरिक सीमाओं को लांघकर एक आधुनिक, आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप ले चुका है। 135 करोड़ रुपये के भारी निवेश और आगामी 14.5 करोड़ रुपये के सब्सिडी लक्ष्यों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में यहाँ की औद्योगिक विकास दर और अधिक तीव्र होने वाली है। सरकार की दूरगामी औद्योगिक नीतियां, जिला प्रशासन का बेहतर क्रियान्वयन और मेरठ के उद्यमियों का अटूट पुरुषार्थ मिलकर एक ऐसे आत्मनिर्भर इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं जो आने वाले दशकों तक देश के खेल निर्यात का नेतृत्व करेगा।

यह औद्योगिक पुनरुत्थान न केवल उत्तर प्रदेश की वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के सपने को साकार करने में एक मुख्य स्तंभ साबित हो रहा है, बल्कि वैश्विक खेल बाजार में भारत की आत्मनिर्भरता और श्रेष्ठता की एक नई स्वर्णिम इबारत भी लिख रहा है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भारती ने बन्ना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सत्य पैलेस(?) एरिया, दिल्ली-31, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भारती, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादस्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/[illegible])

छतरपुर में फिर तेज हुआ चिता आंदोलन, आदिवासी महिलाओं ने नदी में उतरकर किया फांसी सत्याग्रह

अशोका एक्सप्रेस

मध्य प्रदेश 7छतरपुर जिले में केन-बेतवा परियोजना के विरोध में आदिवासियों का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। 3 जुलाई से बराना नदी किनारे, कूपी गांव के पास चल रहे आंदोलन में मिट्टी सत्याग्रह, जल सत्याग्रह के साथ अब ÷फांसी सत्याग्रह÷ भी किया जा रहा है।

आंदोलन के दौरान आदिवासी महिलाओं ने नदी में उतरकर अपने गले में फंदा डालकर विरोध जताया और ÷न्याय दो या मार दो÷ के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ऐसा विकास स्वीकार नहीं है जिसमें हजारों परिवारों का जीवन, जमीन और जंगल उजड़ जाए।

प्रभावित आदिवासी परिवारों की प्रमुख मांगें हैं कि उन्हें उचित पुनर्वास दिया जाए, मुआवजे में महिला और पुरुषों के बीच समानता रखी जाए, भुगतान में हुई कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो, मानसून के दौरान जबरन तोड़फोड़ रोकी जाए और वन अधिकार कानून का पूरी तरह पालन किया जाए।

जानकारी के अनुसार, छतरपुर जिले में करीब 5,288 परिवार और पन्ना जिले में लगभग 1,400 परिवार विस्थापन की स्थिति का सामना कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या गोंड और कोल आदिवासी समुदायों की बताई जा रही है। वहीं, पन्ना टाइगर रिजर्व के करीब 10,500 हेक्टेयर जंगल के प्रभावित होने की बात भी सामने आ रही है।

आंदोलनकारियों का सवाल है कि विकास जरूरी है, लेकिन उसकी कीमत आखिर कौन चुका रहा है? उनका कहना है कि परियोजनाओं के साथ प्रभावित लोगों के अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

अब नजर प्रशासन और सरकार के अगले कदम पर है कि प्रभावित परिवारों की मांगों पर क्या समाधान निकाला जाता है।

केजरीवाल आज जंतर-मंतर पर वांगचुक से मिलेंगे, आप ने लोगों से भी प्रदर्शन में शामिल होने को कहा

नई दिल्ली आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरुवार को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात करेंगे। पार्टी विधायक संजीव झा ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने लोगों से कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में शामिल होने का आग्रह किया। झा ने बताया कि यह प्रदर्शन देश के युवाओं के लिए पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है। इसका लक्ष्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो संदेश साझा किया।

झा ने कहा कि वांगचुक 17 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। वह किसी निजी हित के लिए नहीं, बल्कि युवा लोगों के भविष्य के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यह प्रदर्शन परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर है। आप नेता ने सोनम वांगचुक को एक समर्पित समाज कार्यकर्ता बताया। उन्होंने अपना जीवन समाज को समर्पित किया है। लद्दाख में जल संरक्षण और सतत पर्वतीय विकास के क्षेत्रों में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। आप नेता ने कहा कि लंबे उपवास के कारण कार्यकर्ता का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक बीती 28 जुलाई से आमरण अनशन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक द्वारा की जा रही भूख हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने कल तक जवाब देने को कहा है। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खण्डपीठ सुनवाई कर रही थी।

टूटते वैवाहिक रिश्तों और दरकते पारिवारिक स्तम्भों के बीच मातृशक्ति से संवाद करेंगे मोहन भागवत

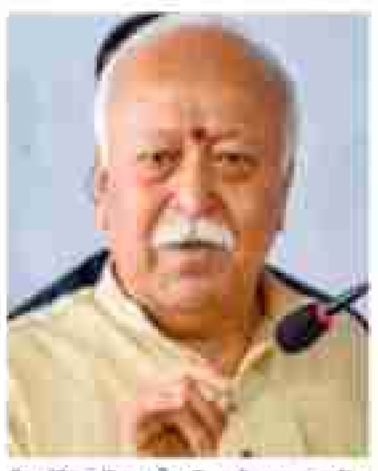

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत 24 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में 500 से अधिक मातृ शक्ति के साथ संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुटुंब प्रबोधन, महिला नेतृत्व और समाज में महिलाओं की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। यह चर्चा दरकते पारिवारिक स्तम्भों को बचाने के संबंध में होगी। जनपथ मार्ग स्थित डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में होने वाले इस संवाद में कुल 700 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसमें संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ-साथ समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, मनोरंजन, खेल और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रमुख महिला शक्तियां शामिल होंगी। डा. भागवत का दो घंटे का प्रबोधन मुख्य आकर्षण होगा। संवाद का आयोजन विश्वमांगल्य सभा द्वारा किया जा रहा है। संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन के लक्ष्य निर्धारित किए है, जिनमें मातृ शक्ति का सहयोग, समर्थन और सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य है। इनमें कुटुंब प्रबोधन एक प्रमुख स्तंभ है। आजकल परिवारों का ताना-बाना बिखरता जा रहा है। संयुक्त परिवारों का विघटन, मूल्यों का ह्रास और सामाजिक विद्रूप्य चेहरा सामने आ रहा है। ऐसे में कुटुंब प्रबोधन की आवश्यकता और भी प्रासंगिक हो गई है। डॉ. मोहन भागवत ने पहले भी कई अवसरों पर महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाना राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने रूढ़िवादी रीति-रिवाजों और परंपराओं से महिलाओं को मुक्त करने की बात कही है। भागवत जी के अनुसार, भारत में महिला माता और शक्ति स्वरूप है। स्त्रियां सृजन की शक्ति हैं, वे रक्षा भी कर सकती हैं और निर्माण भी। भारतीय सभ्यता महिलाओं को समाज की नैतिक और सांस्कृतिक रीढ़ मानती है। समाज में महिलाओं की भूमिका हमेशा से केंद्र बिंदु रही है। घर-परिवार से लेकर राष्ट्र निर्माण तक वे अग्रणी रहती आई है। लेकिन आधुनिक चुनौतियों जैसे परिवारों के टूटने, मूल्यहीनता और सामाजिक परिवर्तनों के बीच मातृ शक्ति का मार्गदर्शन और नेतृत्व अत्यंत जरूरी है। संघ के शताब्दी वर्ष में यह संवाद न केवल महिलाओं को प्रेरित करने वाला होगा, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है और इसमें शामिल होने वाली महिलाएं उत्साह से भरी हुई है।

,आप नेता सौरभ भारद्वाज की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, मानहानि मामले में प्रवेश वर्मा ने अदालत में पेश किए साक्ष्य

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर मानहानि शिकायत में बुधवार को शिकायत पक्ष के दो गवाहों के बयान दर्ज किए। दोनों गवाहों ने अदालत में कहा कि सौरभ भारद्वाज की इंटरनेट मीडिया पोस्ट देखकर उन्हें गहरा झटका लगा और इससे प्रवेश वर्मा व उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। मामले में अब तीसरे गवाह का बयान 25 जुलाई को दर्ज किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल की अदालत में शिकायतकर्ता की ओर से कुलभूषण जैन और शक्ति सिंह सहायका के बयान दर्ज किए गए। दोनों गवाहों ने कहा कि उन्होंने सौरभ भारद्वाज की इंटरनेट मीडिया पोस्ट और वीडियो देखी थी, जिसके बाद उन्होंने प्रवेश वर्मा से इस संबंध में जानकारी ली। प्रवेश वर्मा ने उन्हें बताया कि उनका एसएस मोटा सिंह स्कूल या उससे जुड़े ट्रस्ट से कोई संबंध नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई तय की है, जब शिकायत पक्ष के तीसरे गवाह का बयान दर्ज किया जाएगा। इससे पहले चार जुलाई को प्रवेश वर्मा ने स्वयं अदालत में बयान दर्ज कराते हुए कहा था कि मई 2026 में सौरभ भारद्वाज ने एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए, जिससे उनकी और उनके परिवार की सामाजिक एवं राजनीतिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा। प्रवेश वर्मा ने अदालत को बताया था कि उनके मित्रों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें इंटरनेट मीडिया पोस्ट के लिंक भेजे। कई परिचितों ने उनसे इन आरोपों के बारे में सवाल भी किए और कुछ लोगों को यह विश्वास हो गया था कि वह स्कूल से जुड़े पॉक्सो मामले में शामिल है। शिकायत में प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि सौरभ भारद्वाज ने झूठा प्रचार किया कि वह एसएस मोटा सिंह स्कूल ट्रस्ट से जुड़े हैं, आरोपित की मदद कर रहे हैं और ट्रस्ट में नियुक्तियों में उनकी भूमिका रही है। प्रवेश वर्मा ने इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनका या उनके परिवार का स्कूल व ट्रस्ट से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कानूनी नोटिस भेजे जाने के बावजूद सौरभ भारद्वाज ने न तो उनसे संपर्क किया और न ही माफी मांगी। शिकायत के साथ प्रवेश वर्मा ने 15 मई 2026 के वीडियो और सौरभ भारद्वाज के एक्स पोस्ट भी अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए हैं।

अमित शाह-राहुल गांधी पर एसआईआर की मांग खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकराई जनहित याचिका

नई दिल्ली। भारतीय न्याय संहिता- 2023 की धारा 106(दो) को लागू नहीं करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता व अधिवक्ता रितु गौबा ने अदालत के समक्ष जब राजनीति संदर्भ व राजनेताओं के उदाहरण देना शुरू किया तो मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने मौखिक टिप्पणी की कि इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाएं। याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि किसी प्रविधान को लागू करने पर चर्चा करना केंद्र सरकार के हित में है और इसलिए सरकार को जब भी उचित और सही लगे, तब अधिसूचना जारी करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किसी ऐसी अधिसूचना के न होने पर, प्रविधान को लागू करने के लिए याचिकाकर्ता की अपील को मंजूरी नहीं दी जा सकती।

दिल्ली में समय पर मिलेंगी सरकारी सेवाएं, जवाबदेही और पारदर्शिता होगी मजबूत

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बुधवार (15 जुलाई) को दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध और आसानी से सेवाएं पाने का अधिकार) विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने कहा है कि यह सरकारी सेवाओं की डिलीवरी में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार है। अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर कोई अधिकारी बिना ठोस वजह सेवा देने में देरी करता है तो उस पर हर दिन 250 रुपये का जुर्माना लगेगा, जो अधिकतम 5000 रुपये तक हो सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस कानून से दिल्ली में प्रशासनिक सुधारों को बड़ा बल मिलेगा। इसका मकसद प्रशासन को नागरिक-केंद्रित और जवाबदेह बनाना है।

मुख्य बातें- जवाबदेही तय: बिना वजह देरी पर अधिकारी पर 250/दिन का जुर्माना, अधिकतम 5,000 तक। दंड से पहले अधिकारी को सफाई का मौका मिलेगा।

नागरिकों का अधिकार: अधिसूचित सरकारी सेवाएं तय समय-सीमा में मिलना अब कानूनी अधिकार होगा।

पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन: आवेदन से लेकर सेवा मिलने तक सब डिजिटल होगा। आवेदन संख्या और स्टेटस की रियल-टाइम ट्रैकिंग होगी, जिससे दफ्तरों के चक्कर कम होंगे। 2011 के कानून की जगह- ये विधेयक 2011 के एक्ट को बदलेगा और तकनीक से सेवाओं को तेज, पारदर्शी बनाएगा।

सीएम रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया ओल्ड क्लोथ्स डोनेशन प्रोजेक्ट, 10 मेट्रो स्टेशनों पर बनेंगे केंद्र

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और डीएमआरसी लेडीज वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन ने पुराने और इस्तेमाल किए गए कपड़ों के संग्रह और रीसाइक्लिंग के लिए दिल्ली सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. डीएमआरसी और डीएलडब्ल्यूओ ने यह समझौता दिल्ली सरकार के स्टेट अर्बन लाइवलीहुड मिशन और कपड़ों के रीसाइक्लिंग से जुड़ी संस्थाओं क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन तथा रेस्पन के साथ किया. इस साझेदारी के तहत दिल्ली में 'ओल्ड क्लोथ्स डोनेशन प्रोजेक्ट' शुरू किया जा रहा है.

इस पहल का उद्देश्य पुराने और इस्तेमाल किए गए कपड़ों को कूड़े के ढेर (लैंडफिल) में जाने से रोकना, कपड़ा कचरे को कम करना और रीसाइक्लिंग तथा अपसाइक्लिंग के जरिए सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार पर्यावरण संरक्षण, प्रभावी कचरा प्रबंधन और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल कपड़ा कचरे को कम करने में मदद करेगी, बल्कि लोगों को स्वच्छ और टिकाऊ दिल्ली बनाने में सक्रिय भागीदार बनने के लिए भी प्रेरित करेगी. इस मौके पर डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार और सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद थे. परियोजना के तहत अर्पण नाम से संग्रह केंद्र दिल्ली मेट्रो के 10 स्टेशनों पर स्थापित किए जाएंगे, जहां लोग अपने घरों के पुराने और अनुपयोगी कपड़े दान कर सकेंगे. इसके अलावा रीसाइक्लिंग और अपसाइक्लिंग से बने उत्पादों की बिक्री के लिए कियोस्क भी लगाए जाएंगे. पहले चरण में अगले कुछ दिनों के भीतर शाहदरा, डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल, मालवीय नगर, हौज खास, द्वारका, मोहन एस्टेट, लाजपत नगर, मयूर विहार फेज-1, पंजाबी बाग वेस्ट और शालीमार बाग मेट्रो स्टेशनों पर अर्पण केंद्र शुरू किए जाएंगे. लोग सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक यहां कपड़े दान कर सकेंगे. मुख्यमंत्री ने बताया कि एकत्रित कपड़ों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाएगा.पहली श्रेणी में वे कपड़े होंगे जिन्हें स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बैग, सजावटी सामान और अन्य उपयोगी वस्तुओं में बदल सकेंगी. दूसरी श्रेणी में वे कपड़े होंगे जो पूरी तरह उपयोग लायक नहीं है. ऐसे कपड़ों को रीसाइक्लिंग के जरिए नए उत्पादों और कच्चे माल में बदला जाएगा. इसके अलावा धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल किए गए कपड़ों और अन्य पवित्र सामग्री का भी सम्मानपूर्वक पुनः उपयोग और रीसाइकिल किया जाएगा, ताकि लोगों की भावनाओं का सम्मान बना रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार टूटी-फूटी मूर्तियों, प्लास्टिक कचरे और अन्य प्रकार के कचरे के लिए भी अलग समाधान विकसित कर रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि यदि हर प्रकार के कचरे के लिए वैज्ञानिक और व्यवस्थित समाधान तैयार किए जाएं, तो दिल्ली को कई जटिल समस्याओं से मुक्त किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि फिलहाल 10 अर्पण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में इस पहल का विस्तार पूरे दिल्ली में किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना कपड़ा प्रदूषण कम करने, टिकाऊ जीवनशैली को बढ़ावा देने और महिलाओं के लिए नए रोजगार अवसर पैदा करने की दिशा में एक अभिनव कदम है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ऐसी व्यवस्था विकसित करना चाहती है, जहां पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास साथ-साथ आगे बढ़ें. सरकारी बयान के अनुसार, इन संग्रह केंद्रों का संचालन स्टेट अर्बन लाइवलीहुड मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं करेंगी. उन्हें कपड़ों की अपसाइक्लिंग और रीसाइक्लिंग की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें. आईएनएस के मुताबिक दान किए गए कपड़ों का एक हिस्सा उन्हें अपसाइक्लिंग के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा. क्लोथ्स बॉक्स फाउंडेशन और रेस्पन एकत्रित कपड़ों की छंटाई, रीसाइक्लिंग और अपसाइक्लिंग की पूरी प्रक्रिया का संचालन करेंगे. इन केंद्रों पर रीसाइक्लिंग और अपसाइक्लिंग से बने उत्पादों की बिक्री भी की जाएगी, जिससे सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल को बढ़ावा मिलेगा.

सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत को अपशब्द कहने वाले लॉ स्टूडेंट गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में किया था हंगामा; पुलिस रिमांड पर भेजे गए

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान हंगामा करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो कानून के छात्रों को गिरफ्तार किया है. दोनों पर अदालत की कार्यवाही में बाधा डालने, अभद्र व्यवहार करने और सुरक्षाकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करने का आरोप है. फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस रिमांड पर है और मामले की जांच जारी है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रबल प्रताप सिंह और चंदर भान के रूप में हुई है. दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले है और लॉ की पढ़ाई कर रहे है. दिल्ली पुलिस के अनुसार, 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर-13 में एक मामले की सुनवाई के दौरान प्रबल प्रताप सिंह ने खुद को याचिकाकर्ता बताकर पेश किया. इस दौरान उसने कथित तौर पर अदालत में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, कागज फेंके और न्यायिक कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की.

सुरक्षाकर्मियों से भी की धक्का-मुक्की

जब कोर्ट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी के साथ धक्का-मुक्की भी की. इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और आगे की कार्रवाई शुरू की गई.

मानसिक जांच में नहीं मिली इलाज की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद दोनों आरोपियों का आईएचबीएएस में मेडिकल परीक्षण कराया गया. डॉक्टरों ने अपनी जांच में बताया कि दोनों को तत्काल किसी मानसिक उपचार की आवश्यकता नहीं है.

आपत्तिजनक पर्चे भी बरामद

जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से आपत्तिजनक शब्दों वाले कुछ पर्चे भी बरामद किए हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन पर्चों का उद्देश्य क्या था और क्या इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश या योजना थी. इस मामले में दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 132, 221, 224, 3(5) समेत अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दो दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया था. फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है.

यमुना डूब क्षेत्र में फिर पनपने लगे अवैध डेयरी फार्म और मवेशियों के ठिकाने, तुरंत कार्रवाई के निर्देश

दिल्ली। यमुना नदी के डूब क्षेत्र (फ्लडप्लेन) में हटाए गए अवैध डेयरी फार्म और मवेशियों के ठिकाने फिर से बन रहे है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की ओर से राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट से यह बात सामने आई है। पर्यावरण कार्यकर्ता गौरी मौलेखी की याचिका पर सुनवाई के दौरान डीपीसीसी ने अदालत को बताया कि मयूर विहार फेज-1 और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास यमुना खादर में कई स्थानों पर दोबारा कब्जे हो गए है। डीपीसीसी के वरिष्ठ पर्यावरण इंजीनियर सुनील कुमार गोयल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अधिकारियों की टीम ने जून और जुलाई 2026 में प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान यमुना के संवेदनशील ओ-जोन में डेयरी फार्मों के कोई पक्के मकान या दीवारें नहीं मिली, लेकिन मयूर विहार में डीएनडी फ्लाईओवर और नमो भारत आरआरटीएस कॉरिडोर के नीचे कई झुग्गियां और घास-फूस से बने अस्थायी तबेले पाए गए। रिपोर्ट के अनुसार, इन स्थानों पर मवेशियों को लकड़ी के खूंटों से बांधा गया था और वहां चारे और गोबर के ढेर मिले। इसके अलावा यमुना के खुले मैदानों में 50 से 60 गाय और भैंस चरती हुई मिलीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये पशु चक चिल्ला गांव के पशुपालकों के हैं। टीम ने कुछ भैंसों को यमुना नदी और हिंडन कट नहर में नहाते हुए भी देखा। इसी तरह न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में भी तीन में से दो स्थानों पर मवेशियों के अस्थायी ठिकाने दोबारा बने हुए मिले। यमुना का डूब क्षेत्र डीडीए के अधिकार क्षेत्र में आता है। डीपीसीसी ने 2 और 6 जुलाई 2026 को डीडीए के भूमि प्रबंधन विभाग को पत्र भेजकर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डीपीसीसी ने कहा है कि डीडीए, नगर निगम (एमसीडी) के पशु चिकित्सा विभाग की मदद से अवैध रूप से रखे गए मवेशियों को जब्त करे, अस्थायी झुग्गियों को हटाए और कार्रवाई रिपोर्ट जल्द ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत करे। प्रदूषण रोकने के लिए डीपीसीसी ने दिल्ली के सभी डेयरी और गौशाला संचालकों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 14 तक पशु रखने वाले डेयरी फार्मों को ग्रीन श्रेणी और 15 या उससे अधिक पशु रखने वाले डेयरी फार्मों को ऑरेंज श्रेणी में रखा गया है। सभी डेयरी संचालकों को 15 दिनों के भीतर प्रदूषण नियंत्रण नियमों के तहत सहमति (कंसेंट) के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया है। नियमों का पालन नहीं करने पर डेयरी को सील करने के साथ बिजली और पानी की आपूर्ति भी बंद की जा सकती है। डूब क्षेत्र (फ्लडप्लेन) को बाढ़ और कब्जों से सुरक्षित बनाने के लिए डीडीए और दिल्ली सरकार ने 22 किलोमीटर लंबे यमुना डूब क्षेत्र की सीमांकन का करीब 75 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में दाखिल ताजा प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, 100 साल में आने वाली संभावित बाढ़ के स्तर को ध्यान में रखते हुए पूरे क्षेत्र में कुल 277 पिलर लगाए जाने है। इनमें से अब तक 206 पिलर लगाए जा चुके है। डीडीए ने अदालत को बताया है कि बाकी पिलर 31 जुलाई तक लग जाएंगे। दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को एनजीटी से राहत मिली है। एनजीटी ने मजनू का टीला (मैगजीन ड्रेन) से ओल्ड रेलवे ब्रिज (नीली छतरी मंदिर क्षेत्र) तक बनी पुरानी बाढ़ सुरक्षा दीवार की मरम्मत और उसे मजबूत करने की अनुमति दे दी है।

राजधानी लखनऊ में दिनदहाड़े एसिड अटैक!

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिनहट क्षेत्र में मंगलवार को एक दुकान के अंदर एक अज्ञात व्यक्ति ने युवक पर कथित तौर पर तेजाब फेंक कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बुधवार को बताया कि हमलावर की तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार, घटना मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे हुई, जब पीड़ित अपने तीन साथियों के साथ दुकान पर मौजूद था। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति दुकान में घुसा और युवक पर तेजाब फेंककर फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि घायल युवक को पहले मल्हौर रोड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान रेफर किया गया। उपचार के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

विश्व युवा कौशल दिवस पर आईटीआई पडरौना में प्रदर्शनी, उत्कृष्ट प्रशिक्षुओं को मिला सम्मान

कुशीनगर।

विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर बुधवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), पडरौना में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत प्रदर्शनी एवं प्रशस्ति-पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सदर विधायक मनीष जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विधायक ने प्रदर्शनी में लगाए गए विभिन्न प्रशिक्षण स्टॉलों का अवलोकन किया और प्रशिक्षुओं द्वारा तैयार उत्पादों एवं परियोजनाओं की सराहना की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की योजनाएं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करा रही हैं। उन्होंने युवाओं से इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। समारोह में विभिन्न ट्रेडों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए गए। वहीं मैक्स हॉस्पिटल, दिल्ली, सीटी हॉस्पिटल, गोरखपुर तथा राणा हॉस्पिटल, गोरखपुर में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रतिष्ठानों, जिनमें त्रिवेणी शुगर मिल और द यूनाइटेड शुगर मिल शामिल हैं, के प्रबंधकों को भी विधायक ने प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता त्रिभुवन नारायण सिंह, प्रमोद गौतम और सौरभ जायसवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके अलावा नोडल प्रधानाचार्य एवं जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन आलोक कुमार मौर्य, राजकीय आईटीआई कसया के प्रधानाचार्य ए.पी. राय, राजकीय आईटीआई हाटा के प्रधानाचार्य पी.एन. शर्मा, वरिष्ठ अनुदेशक बी.एन. गुप्ता, जिला कौशल प्रबंधक अभय श्रीवास्तव, कौशलेन्द्र प्रताप सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक विनय पांडेय, आर्यन श्रीवास्तव, मुकुल कुमार, पीयूषकांत सिंह सहित जनपद के सभी राजकीय आईटीआई के अधिकारी, कर्मचारी, प्रशिक्षक, प्रशिक्षु एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।यदि इसे दैनिक जागरण या अमर उजाला की अधिक संक्षिप्त (250-300 शब्द) शैली में चाहिए, तो मैं वह संस्करण भी तैयार कर सकता हूँ।

विकसित साथी पोर्टल पर बीज विक्रेताओं का ऑनलाइन पंजीकरण 25 जुलाई तक अनिवार्य

कुशीनगर।

जनपद के किसानों को उच्च गुणवत्ता एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित विकसित साथी पोर्टल पर सभी बीज विक्रेताओं का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य बीज उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल एवं ट्रैसेबल बनाना है, जिससे बीज की गुणवत्ता और प्रामाणिकता का प्रभावी सत्यापन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि जनपद के सभी पंजीकृत बीज विक्रेताओं को अपने बीज अनुज्ञापन (लाइसेंस), पैन कार्ड, आधार विवरण, जीएसटी विवरण तथा प्रतिष्ठान से संबंधित अन्य आवश्यक अभिलेख विकसित साथी पोर्टल पर अपने लॉग-इन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से अपलोड करने होंगे। यदि पंजीकरण अथवा दस्तावेज अपलोड करने में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो संबंधित विक्रेता विकास भवन स्थित जिला कृषि कार्यालय, रवीन्द्रनगर, कुशीनगर में संपर्क कर उसका निराकरण करा सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी ने निर्देश दिया है कि यह प्रक्रिया हर हाल में 25 जुलाई 2026 तक पूरी कर ली जाए। निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर पंजीकरण और आवश्यक दस्तावेज अपलोड न करने वाले बीज विक्रेताओं के विरुद्ध बीज लाइसेंस के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की वैधानिक कार्यवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विक्रेता की होगी।

पड़री मेंदिया में हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिरा, बड़ा हादसा टला

नेबुआ नौरंगिया (कुशीनगर)।

क्षेत्र के पड़री मेंदिया गांव में बुधवार दोपहर जर्जर हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर मुख्य मार्ग पर गिर गया। संयोगवश उस समय सड़क पर आवाजाही कम होने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरातफरी का माहौल बन गया और तत्काल बिजली आपूर्ति बंद करानी पड़ी।जानकारी के अनुसार खजुरी-बेलवा घाट मार्ग पर पड़री मेंदिया गांव के सामने से गुजर रही हाईटेंशन लाइन का तार अचानक टूटकर सड़क पर गिर गया। तार गिरते ही आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए राहगीरों को मौके से दूर रखा तथा विद्युत विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही संबंधित फीडर की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त हाईटेंशन लाइन काफी समय से जर्जर अवस्था में है। उनका आरोप है कि कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद मरम्मत नहीं कराई गई। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते जर्जर तारों और पोलों को नहीं बदला गया तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस संबंध में विद्युत उपकेंद्र कोटवा के एसडीओ सुनील पाल ने बताया कि हाईटेंशन लाइन का तार टूटने की सूचना मिलते ही बिजली आपूर्ति बंद करा दी गई है। विभाग द्वारा मरम्मत कार्य शुरू करा दिया गया है और जल्द ही क्षतिग्रस्त तार को बदलकर आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

प्राथमिक विद्यालय पुर्नाछापर पहुंचे बीडीओ, मिड-डे मील चखकर परखी गुणवत्ता

बच्चों के साथ बैठकर किया भोजन, पढ़ाई, उपस्थिति और कायाकल्प कार्यो का लिया जायजा-

भटनी देवरिया।

खंड विकास अधिकारी साबिर अनवर ने प्राथमिक विद्यालय पुर्नाछपर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, बच्चों की उपस्थिति, पठन-पाठन व्यवस्था तथा विद्यालय में चल रहे कायाकल्प कार्यों का जायजा लिया। बीडीओ ने बच्चों के साथ बैठकर मध्याह्न भोजन किया और भोजन की गुणवत्ता की जांच की। इसके बाद उन्होंने कक्षाओं में जाकर बच्चों से सवाल पूछे तथा शिक्षण व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद बीडीओ ने ग्राम पंचायत परसौनी पहुंचकर प्राप्त शिकायत के संबंध में स्थलीय जांच की और संबंधित लोगों से जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा शिकायतों का निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

25 वर्षों से बदहाल सड़क पर फूटा वार्डवासियों का गुस्सा, जिलाधिकारी से लगाई गुहार

भटनी देवरिया। नगर पंचायत भटनी के हतवा रेलवे कॉलोनी वार्ड नंबर-3 की जर्जर मुख्य सड़क को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश सामने आया है। वार्डवासियों ने जिलाधिकारी देवरिया को सामूहिक हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र भेजकर सड़क के शीघ्र निर्माण की मांग की है। शिकायतकर्ता असलम अंसारी ने बताया कि लगभग 25 वर्षों से वार्ड की मुख्य सड़क बदहाल स्थिति में है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे होने के कारण आए दिन राहगीर, स्कूली बच्चे और दोपहिया वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भर जाने से स्थिति और गंभीर हो गई है। लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है, जबकि जलभराव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। वार्डवासियों का आरोप है कि इस समस्या की शिकायत कई बार की गई, लेकिन आश्वासन के अलावा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। प्रार्थना पत्र में जिलाधिकारी से मांग की गई है कि जनहित को देखते हुए संबंधित विभाग को तत्काल सड़क की मरम्मत अथवा नवनिर्माण के निर्देश दिए जाएं, ताकि क्षेत्रवासियों को वर्षों पुरानी इस समस्या से राहत मिल सके। प्रार्थना पत्र पर असलम अंसारी,कादिर अंसारी,ताज अंसारी,अख्तर हुसैन,मजहर हसन, सुधीर कुमार, शाली अहमद, सुदामा प्रसाद, राधिका गुप्ता सहित अनेक वार्डवासियों के हस्ताक्षर हैं।इस पत्रक देने के दौरान सभासद प्रतिनिधि लालबिहारी प्रजापति भी मौजूद रहे।

डायट में एफएलएन प्रशिक्षण का आगाज, बुनियादी शिक्षा को मजबूत करेंगे शिक्षक

कक्षा एक से तीन तक के बच्चों में भाषा और गणितीय दक्षता बढ़ाने पर जोर

देवरिया। प्राथमिक शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कवायद तेज हो गई है। मंगलवार को रामपुर कारखाना स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में सीमैट एवं एससीईआरटी के संयुक्त तत्वावधान में पांच दिवसीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (एफएलएन) प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन डायट प्राचार्य डॉ. रामजियावन मौर्य ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने उपस्थित एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को पढ़ना, लिखना और बुनियादी गणना सिखाना ही पूरी शिक्षा व्यवस्था की नींव है। प्रशिक्षण सत्र के दौरान शिक्षकों को पारंपरिक ढर्रे से अलग हटकर बाल-केंद्रित शिक्षण विधियों, गतिविधि-आधारित अधिगम और नवीन मूल्यांकन तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान दिया जा रहा है। कलेक्ट्रेट और शिक्षा विभाग के उच्च मानकों के अनुरूप, इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में पठन-पाठन को अधिक रोचक, प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाना है। प्रशिक्षण प्रभारी अनिल कुमार तिवारी ने सत्र की महत्ता को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि यदि कक्षा एक से तीन तक के बच्चे भाषा की समझ और गणित के बुनियादी जोड़-घटाव में पिछड़ जाते हैं, तो आगे की कक्षाओं में उनकी राह कठिन हो जाती है। ऐसे में शिक्षकों की भूमिका सबसे संवेदनशील और निर्णायक है। इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में संदर्भदाता के रूप में राकेश कुमार सिंह, उपेंद्र उपाध्याय, आदित्य नारायण गुप्ता और शीला चतुर्वेदी द्वारा विभिन्न सत्रों का संचालन किया जा रहा है। डायट प्रवक्ताओं में सतीश मिश्र, परशुराम यादव, आफताब अहमद, गोविंद गुप्ता, जितेंद्र कुमार और सीमा कुमारी सहित सभी प्रतिभागी सक्रिय रूप से शामिल रहे। कार्यशाला के अंत में सभी शिक्षकों ने प्रशिक्षण के दौरान सीखे गए नए कौशल और तकनीकों को अपने-अपने विद्यालयों में अक्षरशः लागू करने का संकल्प लिया, ताकि ग्रामीण अंचलों के प्राथमिक विद्यालयों में गुणात्मक शैक्षिक सुधार दिख सके।

दो बच्चों की मां की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या का आरोप

मायके पक्ष थाने में दी तहरीर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज

(मृतिका अनु का फाइल फोटो)

भटनी देवरिया।

थाना क्षेत्र के साहोपार महुआवारी गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मायके पक्ष ने पति, सास और ससुर पर अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बलुआ अफगान (मधवापुर टोला) निवासी बिजान्ती देवी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी पुत्री अनू की शादी 11 जून 2022 को साहोपार महुआवारी निवासी दुर्गेश गोंड के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति दुर्गेश गोंड, ससुर रामदेव गोंड और सास राजकुमारी अतिरिक्त तीन लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करते थे। कई बार समझाने के बावजूद उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। तहरीर के अनुसार, मंगलवार रात विवाहिता की तबीयत खराब होने की सूचना मिली। बुधवार सुबह परिजन ससुराल पहुंचे तो अनू मृत अवस्था में मिली। मायके पक्ष का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि विवाहिता के शरीर पर चोट के निशान थे।मौके पर पहुँची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए देवरिया भेज दिया। इस सम्बंध में जब थानाध्यक्ष पंकज कुमार गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

राज्य मंत्री गौरव गौतम ने राष्ट्रीय ग्रेडिंग में श्रेष्ठ स्थान पाने वाली प्रदेश की 5 सरकारी आईटीआई को किया सम्मानित

चंडीगढ़ । हरियाणा के युवा एवं उद्यमिता राय मंत्री श्री गौरव गौतम ने आज पंचकूला स्थित हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के सभागार में आयोजित राय स्तरीय समारोह में हरियाणा की 5 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को राष्ट्रीय स्तर की ग्रेडिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया। यह समारोह विश्व युवा कौशल दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य राय के तकनीकी और व्यावहारिक शिक्षा ढांचे की इस अभूतपूर्व उपलब्धि को रेखांकित करना था। इस दौरान राय मंत्री श्री गौरव गौतम ने प्रदेशवासियों और युवाओं को विश्व युवा कौशल दिवस की बधाई व शुभकामनाएं दी और कहा कि पीएम सेतु योजना के अंतर्गत विभाग का लक्ष्य प्रदेश के 20 हजार युवाओं को देश की अग्रणी व प्रतिष्ठित औद्योगिक कंपनियों के साथ जोड़ना है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को उद्योगों की तात्कालिक मांग के अनुसार आधुनिक विधाओं में निपुण किया जाएगा, जिससे वे सीधे रोजगार प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में राय सरकार युवाओं के कौशल विकास और उनके लिए रोजगार के बेहतर अवसर सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर राय मंत्री ने राष्ट्रीय स्तर पर देश में हरियाणा का नाम रोशन करने वाली 5 राजकीय आईटीआई संस्थानों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष रूप से सराहा और बधाई दी। गवर्नमेंट आईटीआई बोड़िया खेड़ा (फतेहाबाद) - राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान, गवर्नमेंट आईटीआई बरवाला (हिसार) - राष्ट्रीय स्तर पर 6वां स्थान, गवर्नमेंट आईटीआई कैथल - राष्ट्रीय स्तर पर 7वां स्थान, गवर्नमेंट आईटीआई पिहोवा - राष्ट्रीय स्तर पर 8वां स्थान, राजकीय महिला आईटीआई सिरसा - राष्ट्रीय स्तर पर 9वां स्थान हासिल किया है। कार्यक्रम के दौरान राय मंत्री ने विभाग की महत्वाकांक्षी व मार्गदर्शक -युवा संवाद- पत्रिका का भी अनावरण किया। इसके साथ ही, प्रशिक्षण और प्रशासनिक स्तर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से उन्होंने पारदर्शी प्रक्रिया से चयनित 60 नवनियुक्त प्रिंसिपलों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने सभी नवनियुक्त अधिकारियों को पूरी निष्ठा, मेहनत और लगन के साथ आईटीआई में प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रेरित किया। श्री गौरव गौतम ने कहा कि वर्तमान युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से लेकर आधुनिक तकनीकी अनुप्रयोगों तक और उन्नत तकनीक से लेकर पारंपरिक सिविल इंजीनियरिंग तक, हर क्षेत्र पूरी तरह हुनर (स्कील) पर आधारित हो गया है। आज के समय में केवल डिग्री नहीं, बल्कि कौशल ही सबसे बड़ा हथियार है। कौशल युक्त युवा ही समृद्ध प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। केंद्र व राय सरकार का साझा लक्ष्य है कि प्रदेश के हर हाथ को हुनर मिले ताकि प्रत्येक युवा एक विकसित भारत के निर्माण का आधार बन सके। इस अवसर पर हरियाणा कौशल विकास मिशन के एचएसडीएम निदेशक श्री सतेंद्र दूहन, प्रबंध निदेशक (एमडी) श्री राजेश गोयल, अतिरिक्त निदेशक श्रीमती कमलप्रीत कौर, श्री संजीव शर्मा तथा सहायक निदेशक श्री मनोज सैनी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सक्षम भारत की वेबसाईड से जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें।